

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी.आई. मामला

फा.सं. 17026/78/2014-एस.आर.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(सी.एस. प्रभाग)

एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 2014

सेवा में,

श्री पवन तिवारी,
अग्रवाल मंडी, टटीरी,
जिला: बागपत, पिन 250601 (उ.प.)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के पी.पी. प्रभाग के माध्यम से प्राप्त हुए आपके दिनांक 02.06.2014 के आर.टी.आई. आवेदन (इस प्रभाग में दिनांक 16.07.2014 को प्राप्त) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। अधोहस्ताक्षरी सी.पी.आई.ओ. से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु सं. 6: पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग केन्द्रीय राज्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

2. यदि आप सी.पी.आई.ओ. के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामतः श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,
3।।३।।५।।५।।
(आशुतोष जैन)
निदेशक(सी.एस.-॥) एवं सी.पी.आई.ओ.
दूरभाष: 23438147

प्रति प्रेषित:-

1. अनुभाग अधिकारी, वी.एस. अनुभाग, पी.पी. प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, तीसरा तल, नई दिल्ली को उनके दिनांक 9.7.2014 के पत्र के संदर्भ में।

2. ~~अनुभाग अधिकारी, आई.टी.एकक, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवेदक के दिनांक 2.6.2014 के आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित।~~

आवेदक की प्राप्ति प्राप्त नहीं है।

१।।३।।५।।

एस.आर.आई.ओ.

आवेदन की प्राप्ति संलग्न है।

एस.ओ. (माई.टी.) अर्म्स्ट्रॉन्ग चार्टर्ड एक्ट्रोफिल्म

प्रधानमंत्री

एडवोकेट
इन्डिया बोर्ड, एल०एल०बी०, टी०इ०एम०
संघीय कार्यकर्ता एवं आर०टी०आई० विशेषज्ञ
जिला नहासंत्री सुदूर प्रक्षेत्र
अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा
जिला बागपत (उ०प्र०)
उपाध्यक्ष—श्री अमरनाथ सेवा समिति (रजिओ)
अग्रवाल मण्डी टटीरी जिला बागपत (उ०प्र०)

निवास — अग्रवाल मण्डी टटीरी
जिला बागपत (उ०प्र०)
पिन कोड— 250601
कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायालय,
परिसर बागपत,
उ०प्र०—250609
मोबाइल नं०— 09058860009

73

पत्रांक :— 60 / 2014

दिनांक :— 02.06.2014

सेवा में

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / मंत्री मण्डल सचिव,

भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 110001 भारत।

पिछले “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” की धारा 6 (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र एवं धारा 6 (3) के प्राविधानों में अन्तर्निहित

श्रीमानजी,

निवेदन यह है कि आदेशक को उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 सम्बित धारा 3 एवं 4 के प्राविधानों के अनुसार नीचे लिखे बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये। सूचना न देने या विलम्ब से देने की स्थिति में हुई अपील/परिवाद/दाद व्यय के हज़े—ख़र्च की पूरी जितनी आपकी स्वयं की होगी तथा सक्षम न्यायालय द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही आपके विरुद्ध अमल में लायी जायेगी।

सूचना शुल्क — अंकन 10/- रु० भारतीय पोर्टल आर्डर सं० 17 एफ- ९.११.८२९ साथ में सलंगन है।

महत्वपूर्ण :— श्रीमान जी यदि प्रार्थी द्वारा नौंगी गयी सूचनाएं किसी अन्य दिनांग या अधिकारी द्वारा धारित हैं तो कृपया प्रार्थी का यह सूचना आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) द्वितीय के परन्तुक के अनुसार सूचना आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के अन्दर सम्बन्धित लोक ग्राहिकारी को प्रेषित कर दें।

सूचना बिन्दु :—

1. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह ने कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया? सूचना प्रदान करें।
2. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया? वह किस भद्र से किया गया सूचना प्रदान करें।
3. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया? वह किसके आदेशों पर किया गया है? सम्बन्धित आदेशों की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (ज) द्वितीय सप्ताहित धारा 3 व 4 के अन्तर्गत प्रदान करें।

4. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम उपरान्त श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उनके मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कुल जितनी धनराशि का व्यय किया गया? वह किसकी सलाह, मत के आधार पर किया गया है, सूचना प्रदान करें।
5. यह कि क्या लोक सभा सदस्य तथा विधान सभा सदस्य पद के निर्वाचन हेतु क्या संसद द्वारा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
6. यह कि क्या पश्चिमी उठोप्र० को अलग राज्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
7. यह कि क्या पश्चिमी उठोप्र० में हाईकोर्ट बैच स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
8. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक भवितव्याता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? सूचना प्रदान करें।
9. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक भवितव्याता अभियान में कुल जितनी धनराशि खर्च की गयी? वह किस-किस भवितव्याता की गयी? सूचना प्रदान करें।
10. यह कि लोक सभा चुनाव वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जागरूक भवितव्याता अभियान में कुल कितनी धनराशि खर्च करने हेतु किस-किस नेर सरकारी संगठन को दी गयी तथा कितनी-कितनी दी गयी? सूचना प्रदान करें।
11. यह कि क्या अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान को निरस्त करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
12. यह कि क्या उठोप्र० में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल में विचाराधीन है? सूचना प्रदान करें।
13. यह कि क्या न्यायालय विधि का निर्माण कर सकता है? सूचना प्रदान करें।
14. यह कि क्या टिल्ली-सहारनपुर वाया शामली रेलवे लाइन को डबल करने का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? सूचना प्रदान करें।
15. यह कि दिल्ली-शामली रेलवे मार्ग से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारतीय रेलवे को घाटा हुआ या मुनाफ़ा हुआ? सूचना प्रदान करें।
16. यह कि क्या अयोध्या-काशी-लखनऊ-सामगंत-हाईकोर्ट रेलवे क्रेसिस नेर ऊपरगामी सेतु बनाने हेतु किस प्रस्ताव करना चाहता है? सूचना प्रदान करें।